

AM

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 92/2021

बलबीर पुत्र बस्तीराम, जाति स्वामी, निवासी झेरली, तहसील-सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

--- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

--- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.05.2020 द्वारा अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बलबीर मु0नं0 1/2020 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

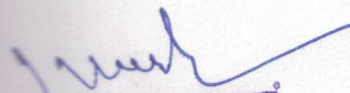
दिनांक 09.03.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 20.05.2020 के विरुद्ध मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्त की ओर से अपील निम्न आधारों सहित पेश है कि निर्णय योग्य अदालत मातहत खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का सही रूप से अवलोकन नहीं किया है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व कब्जे बाबत अन्य दस्तावेज का सही रूप से अवलोकन नहीं कर अपीलान्त के विरुद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के उक्त भूमि पर पक्के आवासीय मकान बने हुए जो 70-80 साल पुराने हैं जिसमें अपीलान्त के पूर्वजों का विवाह, खुशियां, बच्चों के जन्म तथा बुजुर्गों के निधन का गम सभी इन मकानात में हुआ है और इस मकान का अपीलान्त का वंशानुगत जुड़ाव है। उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की गई है, जो गलत है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है। अपीलान्त को उक्त भूमि से बेदखल न कर नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जहां विधि का सारभूत तथ्य निहित हो वहां सरसरी प्रोसेडिंग के द्वारा कानूनन: किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता उक्त कानूनी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। मूर्ति मन्दिर की भूमि से बेदखल करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत ही नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जा सकता है। उक्त कानूनी प्रावधानों की अदालत मातहत ने की है। अपीलान्त से उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। जहां लगान लिया जाकर खातेदारी व काश्त के अधिकार दिये जाते हैं वहां धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा


जिला कलक्टर झुंझुनू

सकती है। अपीलान्त की स्थिति खातेदार की है, न की अतिक्रमी की है। उक्त कानूनी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। अपीलान्त के द्वारा भूमि खसरा नं० 506 रकबा 0.39 हैक्टर के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती का दावा कर रखा है जिसके मु०नं० 27/2020 है जो विचाराधीन है। उक्त भूमि अपीलान्त की पैतृक दादालाई कृषिभूमि है उक्त विवादित भूमि के तत्कालीन काश्तकार उपकृषक बस्तीराम पुत्र जीताराम के विधिक वारिसान है मन्दिर श्री हनुमान जी वाके सा देह की पूजा अर्चना के लिए ठिकाना के समय से ही उक्त भूमि अपीलान्त के पूर्वज काश्त करते रहे तथा वर्तमान में अपीलान्त व उसका परिवार काश्त कर रहा है। अपीलान्त के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। निर्णय अदालत मातहत का इलीगल, परवर्स एवं डिफेंडेट ज्यूरिडिक्शन है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 20.05.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्त सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का सही रूप से अवलोकन नहीं किया है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत सपथ पत्र व कब्जे बाबत अन्य दस्तावेज का सही रूप से अवलोकन नहीं कर अपीलान्त के विरुद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के उक्त भूमि पर पक्के आवासीय मकान बने हुए जो 70-80 साल पुराने है जिसमें अपीलान्त के पूर्वजों का विवाह, खुशियां, बच्चों के जन्म तथा बुजुर्गों के निधन का गम सभी इन मकानात में हुआ है और इस मकान का अपीलान्त का वंशानुगत जुड़ाव है। उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की गई है, जो गलत है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है। अपीलान्त को उक्त भूमि से बेदखल न कर नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जहां विधि का सारभूत तथ्य निहित हो वहां सरसरी प्रोसेडिंग के द्वारा कानूननः किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता उक्त कानूनी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। मूर्ति मन्दिर की भूमि से बेदखल करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत ही नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जा सकता है। उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी अदालत मातहत ने की है। अपीलान्त से उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। जहां लगान लिया जाकर खातेदारी व काश्त के अधिकार दिये जाते हैं वहां धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलान्त की स्थिति खातेदार की है, न की अतिक्रमी की है। अपीलान्त के द्वारा भूमि खसरा नं० 506 रकबा 0.39 हैक्टर के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती का दावा कर रखा है जिसके मु०नं० 27/2020 है जो विचाराधीन है। उक्त भूमि अपीलान्त की पैतृक दादालाई कृषिभूमि है उक्त विवादित भूमि के तत्कालीन काश्तकार उपकृषक बस्तीराम पुत्र जीताराम के विधिक वारिसान है मन्दिर श्री हनुमान जी वाके सा देह की पूजा अर्चना के लिए ठिकाना के समय से ही उक्त भूमि अपीलान्त के पूर्वज काश्त करते रहे तथा वर्तमान में अपीलान्त व उसका परिवार काश्त कर रहा है। अपीलान्त के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 20.05.2020 को निरस्त फरमाया जावे।


जिला कलक्टर मुन्सुन

14

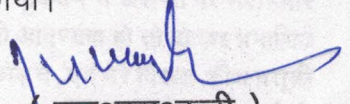
विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम झेरली स्थित विवादित भूमि ख0न0 506 रकबा 0.39 है0 किस्म मंदिर श्री हनुमानजी मे से 0.014 हैक्टर जो कि मंदिर श्री हनुमानजी की भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर खातेदारी की भूमि है एवं अपीलान्ट मंदिर का पुजारी है। अपीलान्ट का परिवार विवादित भूमि में 80 साल से काबिज है। पुजारी को मंदिर भूमि में से नियमानुसार बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट के विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की कार्यवाही नहीं की जा सकता है अदालत मातहत को प्रकरण में धारा 183 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। पूर्व में अदालत हाजा द्वारा इसी भूमि में से पक्के निर्माण को छोड़कर शेष भूमि के अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आलौच्य आदेश दिनांक 08.06.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम झेरली स्थित विवादित भूमि ख0न0 506 रकबा 0.39 है0 किस्म मंदिर श्री हनुमानजी मे से 0.014 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। मंदिर भूमि पर अदालत मातहत द्वारा राजकीय भूमि मानकर राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार सही कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि पूर्व में अदालत हाजा द्वारा इसी भूमि में से पक्के निर्माण को छोड़कर शेष भूमि के अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2020 को उचित नहीं मानते हैं। अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ विवादित भूमि पर पक्के निर्माण को छोड़कर शेष भाग पर बेदखली की कार्यवाही करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं